कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान.................................. 7
भाजपा पूर्वी क्षेत्र बैठक.. 10

सरकार की उपलब्धियां

डिजिटल इंडिया सप्ताह.. 11
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिली 50 हजार करोड़ की मंजूरी........ 13
केंद्र सरकार ने देश में छह नये आईआईएम स्थापित करने की मंजूरी दी..... 14

वैचारिकी

भारतीय जनसंघ ही क्यों ?
डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी... 15

श्रद्धांजलि

भाजपा सांसद दिलीप सिंह भूरिया का देहावसान.................................. 16

लेख

सामाजिक-आर्थिक तथा जाति जनगणना का संदेश
– **अरुण जेटली**... 17
बिहार : जंगलराज बनाम विकास-राज
– **संजीव कुमार सिन्हा**.. 18

अन्य

आपातकाल के संघर्ष को याद रखना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है............. 20
अमरुत, स्मार्ट सिटी मिशन और सभी के लिए मकान (शहरी) योजना..... 22
जगन्नाथ राव जोशी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे 26
पांच राज्यों की 6 विधान सभा सीटों पर उपचुनाव................................. 27
भाजपा अध्यक्ष ने किया पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गठन.............................. 28
भाजपा संगठन में नई नियुक्तियों की घोषणा.. 29

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को **जगन्नाथ रथ यात्रा** की हार्दिक शुभकामनाएं!

मदद की भावना

कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कलकत्ता के एक सेठ महादेव प्रसाद मतवाला बहुत मानते थे। वे उनकी हर सुख-सुविधा का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने निराला जी को बेहद कीमती व गरम दुलाई भेंट की। वे जाड़ों में उस दुलाई को लपेट कर रखते थे। एक दिन कड़ाके की सर्दी में वे दुलाई ओढ़ कर सेठ जी के दफ्तर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भिखारी ठिठुरता हुआ दिखाई दिया। उसे इस हालत में देखकर निराला जी दुखी हो उठे। उन्होंने तुरंत वह दुलाई भिखारी को ओढ़ा दी।

भिखारी को दुलाई ओढ़ते ही गर्माहट का एहसास हुआ और वह बेहद खुश होकर निराला जी को अनेक आशीष देने लगा। यह सारा नजारा मतवाला प्रेस का एक कर्मचारी देख रहा था। उसने सारी बात अपने मालिक को बताई। सेठजी तुरंत बाहर आए और उन्होंने देखा कि निराला जी को भेंट की गई दुलाई एक भिखारी ओढ़े बैठा है। वह निराला जी से बोले, 'यह आपने क्या किया? इतनी महंगी दुलाई एक भिखारी को दान में दे दी?'

सेठ जी की बात सुनकर निराला जी बोले, 'आप जैसे महानुभाव के होते हुए दुलाई तो फिर आ जाएगी, लेकिन यदि सर्दी से ठिठुरते हुए इस भिखारी की जान चली गई तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसका पाप मुझे भी लगेगा कि मैंने देखकर भी एक जरूरतमंद की मदद नहीं की। इसलिए मदद करने से पहले मदद की भावना का विकास होना बेहद जरूरी है। मैं तो खुद में यही भावना विकसित करने का प्रयास कर रहा था।' निराला जी की बात पर सेठ जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने दूसरे भिखारियों को भी गर्म कपड़े दान किए ।

संकलन : रेनू सैनी
(नवभारत टाइम्स से साभार)

पाथेय

हमारा व्रत

जिनके सामने रोजी और रोटी का सवाल है, जिन्हें न रहने के लिए मकान है, न तन ढकने को कपड़ा, अपने मैले बच्चों के बीच आज वे दम तोड़ रहे हैं। गांवों और शहरों के इन करोड़ों निराश भाई-बहिनों को सुखी व संपन्न बनाना हमारा व्रत है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

विकसित, समृद्ध एवं लोकतांत्रिक भारत के लिए भाजपा

समाधकीय

भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल बन चुका है। सदस्यता अभियान जो 10 करोड़ के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था, इस लक्ष्य को भी पार कर 11 करोड़ सदस्य बनाने में सफल रहा। यह एक अत्यधिक सफल अभियान था जो दिन प्रतिदिन भाजपा के प्रति बढ़ते जनविश्वास को परिलक्षित करता है। जब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 10 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य निर्धारित किया था तब अनेक शंकाएं थीं क्योंकि यह बहुत मुश्किल कार्य प्रतीत होता था। लेकिन यह नेतृत्व की दूरदृष्टि, उस इतिहास का दोहराया जाना जिसमें भाजपा ने कठिन से कठिन लक्ष्य को बेधा है तथा कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता का ही परिणाम था। न केवल यह लक्ष्य पार्टी ने प्राप्त किया बल्कि उससे भी एक करोड़ अधिक सदस्य बनाए। इससे विश्व को यह भी पता चला कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल भी है। यह लोकतंत्र की भी जीत है क्योंकि इससे पूर्व विश्व के सबसे बड़े राजनैतिक दल का श्रेय एकदलीय व्यवस्था वाला कम्युनिस्ट देश चीन के पास था। यह पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

सदस्यता अभियान केवल एक अभियान मात्र नहीं था जिसमें सदस्यता कर अपना कार्य समाप्त मान लिया जाय। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वृहत योजना एवं व्यापक रचना की गई है। यह प्रक्रिया का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। यह पूरी तरह से एक 'संगठन शास्त्र' पर आधारित है जो पूरे विश्व के लिए अद्‌भुत है। अभी महासंपर्क अभियान चल रहा है। महासंपर्क अभियान का लक्ष्य सभी सदस्यों से संपर्क करना है। मानवीय संपर्क के साथ-साथ पार्टी की विचारधारा नीतियां एवं कार्यक्रमों से सदस्यों को परिचित कराना भी इसका कार्य है। सदस्यता अभियान के दौरान तकनीक का भरपूर सदुपयोग किया गया था। 'मिस्ड-कॉल' तथा 'ऑन लाईन' जैसे पारदर्शी एवं प्रामाणिक माध्यमों से सदस्यता अभियान को भारी बल मिला। महासंपर्क अभियान ऐसे सभी सदस्यों से भी संपर्क कर उनको पार्टी से परिचित करा उनके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने कार्य कर रही है। यह सदस्यों से संबंध मजबूत कर उनके संबंध में डाटा संग्रहित करने का महत्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य जितना परम्परागत है उतना ही आधुनिक भी। इससे भविष्य में कार्ययोजना के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में तीव्रता से सदस्यों का सहयोग लिया जा सकेगा।

महासंपर्क अभियान के बाद महाप्रशिक्षण अभियान की योजना है। यह एक वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें 15 लाख सदस्यों को मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रशिक्षित किया जायेगा। 30 जून से 2 जुलाई 2015 को इस संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम की रचना विभिन्न स्तरों को ध्यान में रख कर की गई है। इस कार्यक्रम में पार्टी का इतिहास, सिद्धांत, विचारधारा, उपलब्धियां, कार्यपद्धति आदि के विषय में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। अब तक कोई भी राजनैतिक दल इतना विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चला पाया है। भाजपा ने ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का निर्माण करना अपना दायित्व माना है जो राष्ट्र निर्माण को समर्पित हो तथा राजनीति को समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा का माध्यम बनायें। महाप्रशिक्षण अभियान से ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायगा जो परम लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम होंगे।

भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनैतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन है। यह एक व्यापक

आंदोलन का अंग है जो दिन-प्रतिदिन और अधिक सुदृढ़ होता जा रहा है। यह विचारधारा एवं सिद्धांत आधारित दल है। इसकी अपनी अनूठी कार्य पद्धति है जिससे पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र जीवन्त एवं स्वस्थ है। अन्य राजनैतिक दल जो समय-समय पर टूटे और बिखरे हैं के विपरीत भाजपा एकजुट होकर मां भारती के चरणों में निरंतर कार्यरत है। भाजपा ने न केवल अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया है बल्कि इसकी कार्यपद्धति भी अक्षुण्ण रही है और ये दोनों समय के साथ विकसित एवं समृद्ध हुए हैं।

पार्टी के कार्य हमेशा इसकी सांगठनिक कार्यपद्धति के अनुरूप रही है। इसने सदस्यता अभियान, सांगठनिक चुनावों इत्यादि को बराबर नियमित एवं सफलतापूर्वक कराया है। यह कारण है कि भाजपा एकमात्र ऐसा राजनैतिक दल है जो स्वतंत्रता के बाद लगातार आगे बढ़ता रहा है और इसे भारी जनविश्वास प्राप्त होता रहा है।

अन्य राजनैतिक दल जो परिवारवाद एवं वंशवाद के इर्द-गिर्द सिमटते रहे हैं भाजपा एकमात्र ऐसा राजनैतिक दल है जो संगठन की अवधारणा में विश्वास करता है और इसके लिये कार्यकर्ता तैयार करता है। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है और यही कारण है कि लोग इसकी तरफ भारी संख्या में आकर्षित हुए हैं।

महासंपर्क एवं महाप्रशिक्षण अभियान नये सदस्यों को संगठन मजबूत करने में सक्षम करेंगे। इसमें कोई शंका नहीं कि भाजपा एक विकसित, समृद्ध एवं लोकतांत्रिक भारत की पार्टी है। ■

गरीबों के जीवन-स्तर में उत्कृष्ट बदलाव हेतु भाजपा कृतसंकल्पित : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 25 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सम्पूर्ण विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने वाली तीन नयी परियोजनाओं- 100 स्मार्ट सिटी का विकास, 500 नगरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन एवं परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) और 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास योजना का शुभारम्भ करने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों योजनाएं गरीबों के उत्थान व कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

ज्ञात हो कि इसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में इन तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। इन तीन परियोजनाओं के परिचालन दिशानिर्देश, नियमों, लागू करने के ढांचे को केंद्र द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय शहरी निकायों के साथ पिछले एक साल के दौरान की गई चर्चा के आधार पर तैयार की गई है। इस योजना के लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान निर्धारित किया गया है। 100 स्मार्ट सिटी पर 48 हजार करोड़ रुपए, 500 नगरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन एवं परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) पर 50 हजार करोड़ रुपए और 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास योजना पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।

श्री शाह ने प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य के प्रति आभार व्यक्त किया कि यह महत्वाकांक्षी योजना आम लोगों की सहभागिता से निर्धारित की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात की भी सराहना की कि हम अपने देश के गरीब लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर्स इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि शहर का विकास कैसे होना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों के विकास, सबके लिए छत और लोगों के जीवन स्तर में उत्कृष्ट बदलाव लाने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि हर शहरी गरीब को इस लायक बनाया जाए कि उनके पास अपना घर हो। श्री शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांतों को पूरी तरह अमल में ला रही है। जिसके परिणामस्वरूप ही चाहे जन-धन योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, या गरीबों का जीवन बीमा करने की योजना हो या मुद्रा बैंक की योजना हो, यह सब गरीबों, मजदूर और किसानों के विकास को केंद्रित कर बनाई गई है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान

लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महाप्रशिक्षण अभियान एक सार्थक प्रयास : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी ने 30 जून एवं 1-2 जुलाई 2015 को प्रशिक्षण-प्रशिक्षक कार्यशाला का एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सदस्यों सहित पार्टी के 250 वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। हरेक राज्य से पांच प्रतिनिधित्व ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जो अपने-अपने राज्यों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने 1 जुलाई को पार्टी के 15 लाख से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए महाप्रशिक्षण अभियान के राष्ट्रीय प्रशिक्षक कार्यशाला का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि महाप्रशिक्षण अभियान पार्टी के भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सार्थक प्रयास है।

उन्होंने इस बात की सराहना की कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में देश के हर कोने से प्रतिनिधि मौजूद हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी के 352 नेता भाग ले रहे हैं। यह महाप्रशिक्षण अभियान तीन चरणों के कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है जो महासदस्यता अभियान और महा जनसंपर्क अभियान से शुरू हुआ था।

श्री अमित शाह ने इस बात पर जोर देते हुये कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से जो 11 करोड़ नए सदस्य पार्टी ने बनाये हैं, यह केवल चुनाव जीतने के लिए एक मशीनरी भर नहीं है, बल्कि हमें इन्हें पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता समूह में इन्हें परिवर्तित करना होगा जो पार्टी के आदर्शों के सिद्धांतों पर भारत में एक सच्चे कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। पार्टी के कार्यकर्ता भी पार्टी की विचारधारा का प्रचार - प्रसार और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि अन्य राजनीतिक दल आम तौर पर या तो कुछ क्रांति के उपरांत गठित किये गए, या कुछ मुद्दों के खिलाफ एक आंदोलन का एक परिणाम के रूप में इसका अभ्युदय हुआ, या फिर राजनीतिक शक्तियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक उपकरणों के रूप में इनका जन्म हुआ लेकिन भारतीय जनसंघ और बाद में भाजपा राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब यह पाया

गया कि अधिकांश नीतियां भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित होने के बजाय पश्चिमी अभिविन्यास या पश्चिमी परिप्रेक्ष्य पर तैयार की जा रही है तो देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर इस पार्टी का गठन किया गया।

पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि यह महसूस किया गया कि इन तीनों अभियानों की अवधारणा पार्टी के विस्तार के लिए निहायत ही जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा किसी और पार्टी के पास इस तरह के समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं है जिसका कि एक और केवल एक उद्देश्य राष्ट्र निर्माण हो।

भारतीय जनता पार्टी की संगठन के अंतिम स्तर तक के नए और पुराने कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी की विचारधारा, आदर्शों और मूल्यों से ओतप्रोत प्रशिक्षण सत्र को एक नियमित प्रक्रिया बनाने की योजना है। उन्होंने इस बात को इंगित करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका अभी तक विभाजन नहीं हुआ और यह केवल एक मजबूत वैचारिक आधार के फलस्वरूप ही हुआ है।

उन्होंने उपस्थित पार्टी नेताओं को याद दिलाते हुए कहा कि पार्टी द्वारा हर कार्यक्रम और आंदोलन आम लोगों के हित में और राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर किया गया है। श्री अमित शाह ने यह भी बताया कि भाजपा एक व्यक्ति या परिवार उन्मुख पार्टी नहीं है और इसलिए नियमित रूप से निचले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव के लिए पार्टी में चुनाव की एक उचित प्रणाली अपनाई जाती है।

पार्टी के विकास और निरंतरता के लिए भौगोलिक दृष्टि के विस्तार के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की संख्या भी एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। इसलिए उनका प्रशिक्षण ज्यादा अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण है ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता का समग्र विकास हो और वे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। प्रशिक्षित पार्टी कार्यकर्ता

महाप्रशिक्षण अभियान के पहले चरण में भाजपा के मंडल इकाईयों को शामिल किया जाना है। देश में लगभग 11000 मंडल इकाई है। दूसरे चरण में जिला स्तर पर शिविर आयोजित किये जायेंगे। तीसरे चरण में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक शिविरों में अधिकतम 150 सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि सदस्यों की संख्या 150 से अधिक होगी तो इसके लिये अतिरिक्त शिविर लगाये जायेंगे। मंडल स्तर पर कार्यक्रम की अवधि दो दिन और एक रात, जिला स्तर पर दो रात और तीन दिन तथा राज्य स्तर पर तीन रात और चार दिनों की होगी। पूरे प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षकों का शिविरों में रहना भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा।

सभी शिविर राज्यों में एक साथ लगाये जायेंगे और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर एक शिविर का आयोजन किया जायेगा। सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम चार महीनों में पूरा हो जाने की उम्मीद है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सभी उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। राज्य की विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रत्येक राज्य में अलग-अलग प्रशिक्षण सत्र होगा। साथ ही केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की उपलब्धियों जहाँ आम लोगों की भलाई तथा देश हित में कई सारे अग्रणी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, के बारे में सक्रिय कार्यकर्ताओं को अद्यतन रखने के लिए भी एक अतिरिक्त सत्र का आयोजन किया जायेगा।

इस गहन प्रशिक्षण अभियान के पूरा होने से भाजपा राजनीतिक संवाद और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करेगी। किसी अन्य पार्टी ने अब तक इस पैमाने पर किसी कार्य को हाथ में नहीं लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव के दिशा निर्देश में विशेषज्ञों का एक दल इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री, साहित्य और योजनाएं तैयार कर रहा है जिसका नाम पार्टी स्तम्भ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जा रहा है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैंगलोर अधिवेशन में इस संबंध में एक समिति की घोषणा की गई थी जिसके सदस्य श्री वी. सतीश, डॉ महेश चन्द्र शर्मा, श्री एल. गणेशन, डॉ आर. बालाशंकर, श्री रामप्यारे पांडे और श्री सुरेश पुजारी हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम एकात्म मानव दर्शन की पार्टी विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले पार्टी के महान द्रष्टा की जन्म शताब्दी वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। श्री मुरलीधर राव ने कहा कि महाप्रशिक्षण अभियान के लिए अधिकांशत: नए सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि हर स्तर पर समाज के प्रमुख नागरिकों को इसमें शामिल किया जाये और समाज के सभी वर्गों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

बेहतर और कुशल तरीके से अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी का नेतृत्व करेंगें और पार्टी के विचारों और सिद्धांतों को जन-जन तक पहुँचाएंगे। प्रशिक्षण का प्रभाव राज्य में जनादेश की प्राप्ति की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पार्टी नेताओं को हर एक कार्यकर्ता तक पहुंचना होगा। इतने बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं तक पहुँचने से हरेक कार्यकर्ता पार्टी का एक ऊर्जावान शुभचिंतक और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बन जायेंगे।

महा प्रशिक्षण अभियान का लक्ष्य मंडल इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चार महीने के भीतर 15 लाख से अधिक पार्टी सदस्यों को प्रशिक्षित करना है। श्री अमित शाह कहा कि इतनी कम अवधि में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा 15 लाख राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का इस तरह का प्रयास अपने आप में अनूठा है और किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के द्वारा ऐसा अभियान अभी तक सम्पादित नहीं किया गया है।

उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव के नेतृत्व में महाप्रशिक्षण अभियान दल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु नेता विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने-अपने राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रारूपों का अनुकरण करके तैयार करें। महाप्रशिक्षण अभियान भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और यह पार्टी को नए क्षेत्रों और समुदायों तक पहुँचने में मदद करेगी।■

भाजपा का तीन दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न

15 लाख नये सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए शुरू हुआ ''महाप्रशिक्षण अभियान''

देश भर के लगभग 15 लाख सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2 जुलाई को अंतिम रूप दे दिया गया। भाजपा वरिष्ठ नेताओं व प्रमुख प्रशिक्षकों की दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को पार्टी के सांस्कृतिक विचार व कार्यक्रम, संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाये रखने के लिए आवश्यक मानदंड, सरकार और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय तथा जनता से जुड़े मुद्दे के प्रति सजग रहने के तरीके से अवगत कराएगी।

भाजपा ने इस कार्यशाला में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए यह तय किया कि पार्टी नए सदस्यों को न सिर्फ भाजपा के इतिहास और कार्यक्रमों से अवगत कराएगी, बल्कि प्रशिक्षण के जरिए कार्यकर्ताओं में देश के प्रति सजग रहने और अपने सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेगी।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सदस्यता अभियान की समाप्ति पर यह ऐलान किया था कि पहले चरण में 15 लाख नये सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उसी क्रम में यहां दिल्ली में पार्टी के प्रमुख केंद्रीय पदाधिकारियों, राज्यों के प्रतिनिधियों व प्रशिक्षण से जुड़े प्रमुख लोगों की कार्यशाला यहां बुलाई गई थी। पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया।

भाजपा ने इस कार्यशाला में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए यह तय किया कि पार्टी नए सदस्यों को न सिर्फ भाजपा के इतिहास और कार्यक्रमों से अवगत कराएगी, बल्कि प्रशिक्षण के जरिए कार्यकर्ताओं में देश के प्रति सजग रहने और अपने सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेगी। इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) रामलाल और उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे भी नए सदस्यों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री पी मुरलीधर राव ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में सदस्यों को अवगत कराने और उस पर अडिग रहते हुए आगे बढ़ने के बारे में प्रशिक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विचारों से बिना समझौता किए पार्टी कार्यकर्ता देश का राजनीतिक एजेंडा तय कर सकते हैं। इस कार्यशाला में यह तय किया गया कि अगले दो महीने में पहले प्रमुख प्रशिक्षकों को विषयवार तैयार किया जाएगा और फिर राज्यवार कार्यकर्ता प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय किया जाएगा। ■

केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएं : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 7 जुलाई को शरत सदन, हावड़ा में पूर्वी क्षेत्र महा-संपर्क बैठक का उद्घाटन किया। पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखण्ड, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इस बैठक में 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो सात क्षेत्रीय महा-संपर्क बैठकों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है।

- **भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में कार्यकर्ताओं का योगदान महत्त्वपूर्ण**
- **केंद्र सरकार ने हर महीने दो की औसत से पिछले एक साल में 24 प्रेरक योजनाएँ लागू की हैं**
- **मोदी सरकार द्वारा किये गये अभूतपूर्व कार्यों को कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के अंतिम मतदाता तक पहुँचाएं।**

श्री अमित शाह ने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए पूरे भारत में 11 करोड़ से अधिक सदस्यता प्राप्त करने की दिशा में दिये गये योगदान के लिए सभी पांच राज्यों के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस सदस्यता अभियान के पहुँच को प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित किया गया था। कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत पर जोर देते हुये पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि अगर सभी 11 करोड़ सदस्यों की पूरी जानकारी पार्टी कंप्यूटर में एकत्रित नहीं किया गया और पार्टी की विचारधारा को इनके दिलों तक पहुँचाया नहीं गया तो कड़ी मेहनत से हासिल इतनी बड़ी उपलब्धि बेकार हो जाएगी। इसलिए सफल पंजीकरण के बाद हम सभी को 31 जुलाई तक महा-संपर्क अभियान के माध्यम से सभी नये सदस्यों तक पहुँचने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगले दो महीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगें और 15 लाख सदस्यों को सितंबर के अंत तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा ताकि वे पार्टी संगठन की नींव को और मजबूत कर सकें जो पार्टी के चुनावी तंत्र को सुदृढ़ करेगा और पार्टी की मुख्य विचारधार 'मजबूत भारत' का निर्माण करेगा। हम एक राष्ट्रवादी कार्यबल का निर्माण कर रहें हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मजबूत संगठन की महत्ता पर बल देते हुये 2016 में पश्चिम बंगाल के चुनावों की ओर इशारा किया और इस बात पर जोर दिया कि यह प्रशिक्षित कार्यबल निश्चित रूप से ममता बनर्जी को हरा पाने में सक्षम सिद्ध होगा। मजबूत संगठन की मदद से हम पंचायत से संसद तक सही प्रशासन देने में सक्षम हो पायेंगें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने हर महीने दो की औसत से पिछले एक साल में 24 प्रेरक योजनाएँ लागू की हैं जो इस प्रकार हैं: जन-धन योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा बैंक, अमरुत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल पुनर्वास योजना, मृदा स्वस्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सागरमल, स्मार्ट सिटी योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम।

मोदी सरकार को बधाई देते हुये श्री अमित शाह ने कहा कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा किये गये अभूतपूर्व कार्यों को प्रत्येक बूथ के अंतिम मतदाता तक पहुँचाएँ। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें महा-संपर्क अभियान को सफल बनाना है और यही हमारी प्रतिबद्धता है।■

सरकार की उपलब्धियां : डिजिटल इंडिया सप्ताह

अब ई-गवर्नेंस नहीं, बल्कि मोबाइल गवर्नेंस

4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को भाजपानीत राजग सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना 'डिजिटल इंडिया' का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर पीएम ने ई-लॉकर सर्विस को भी लॉन्च किया। दरअसल, केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के जरिए सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना चाहती है और ई-गर्वनेंस को बढ़ावा देना और पूरे भारत को इंटरनेट से कनेक्ट करना इस मुहिम का मुख्य लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन से अब ई-गवर्नेंस नहीं बल्कि एम-गवर्नेंस यानी मोबाइल गवर्नेंस का रास्ता आसान होगा। यही नहीं, डिजिटल इंडिया कैंपेन में कॉरपोरेट सेक्टर 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इससे 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

पहली जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में भाजपानीत राजग सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना 'डिजिटल इंडिया' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया से मोबाइल गर्वनेंस का रास्ता आसान होगा तथा सरकारी सुविधाएं आसानी से लोगों का उपलब्ध होंगी। डिजिटल इंडिया से भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी और देश के विकास की गति और तेज होगी। इस अवसर पर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जो घोषणाएं हुई, उनके अनुसार मात्र कॉरपोरेट सेक्टर 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा और इससे 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज भारत के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वह प्राचीन सभ्यता है और जनसांख्यिकी लाभ के साथ 125 करोड़ लोगों का देश है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक द्वारा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के बीच डिजिटल-अंतर को बाधा बनने की अनुमति नहीं देने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने ई-गर्वनस तथा मोबाइल

डिजिटल इंडिया की प्रमुख बातें

- ब्रॉडबैंड हाइवे - सड़क हाइवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाइवे से शहरों को जोड़ा जाएगा।
- सभी नागरिकों की टेलीफोन सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम जिसके तहत इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- ई-गवर्नेंस - इसके अंतर्गत तकनीक के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाया जाएगा।
- ई-क्रांति - इसके तहत विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोगों को मुहैया कराया जाएगा।
- इंफोर्मेशन फॉर ऑल यानी सभी को जानकारियाँ मुहैया कराई जाएंगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन - सरकार का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल-पुर्जों के आयात को शून्य करना है।
- आईटी फॉर जॉब्स यानी सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अधिक नौकरियां पैदा की जाएंगी।

गर्वनेंस के बारे में अपने विजन को स्पष्ट किया। मोबाइल पर सभी महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक डिजिटल भारत का सपना देखता हूं, जहां उच्च गति के डिजिटल हाईवे देश को जोड़े, 1.2 अरब जुड़े भारतीय नवाचार को प्रेरित करें, टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करे कि नागरिक-सरकार संवाद बाधित न हो पाए। प्रधानमंत्री ने भारतीय आईटी उद्योग नेतृत्व से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सैटेलाइट लांच करने के लिए भारत की आलोचना की जाती थी, लेकिन अब यह माना जाता है कि यह सैटेलाइट आम जन के लिए मददगार है, उदाहरण के लिए मौसम का सटीक अनुमान व्यक्त करके किसानों की मदद की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य सामान्य-जन के जीवन को सुधारना है। उन्होंने कहा कि भारत भले ही औद्योगिक क्रांति में चूक गया हो, लेकिन भारत आईटी क्रांति से नहीं चूकेगा। उन्होंने युवाओं से नवाचार में शामिल होने का अनुरोध किया और कहा कि 'डिजाइन इंडिया' उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 'मेक इन इंडिया'।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से करोड़ों देशवासियों का सपना साकार होगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि बच्चा भी मोबाइल की ओर आकर्षित हो रहा है। अब वह बड़ों की जेब से मोबाइल खींचता है। बच्चा भी डिजिटल ताकत को समझता है। उन्होंने कहा कि समय की मांग है, हम इस बदलाव की जरूरत को समझें और आगे बढ़ें। पहले लोग नदियों के किनारे पर बसते थे, फिर हाइवे जहां बने वहां शहर बसा, लेकिन अब मानव जाति वहां बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जो भी विरासत में मिला है उसके साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़ना होगा। देश में 25-30 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, यह काफी बड़ी संख्या है। लेकिन भारत में इससे वंचित लोग भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब डिजिटल इंडिया को वहां ले जाना है जहां के लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है। जो वंचित रहेंगे वो पिछड़े रह जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल डिवाइड की वजह से भविष्य में समाज में खाई बन जाएगी। इसलिए गरीब से गरीब तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। यह सुविधा गांव के गरीब तक पहुंचनी चाहिए। तभी वह विकास का लाभ ले पाएगा। इसलिए सरकार दूर-सुदूर गांव में इस सुविधा को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। ताकि वह अपनी जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग कर सके। श्री मोदी ने डिजिटल ताकत का महत्व बताते हुए कहा कि आज बच्चा भी गूगल गुरु की सहायता लेना जानता है। मिनिमन गवर्नमेंट-मैक्सीमम गवर्नेंस में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। ई-गवर्नेंस जल्दी ही एम-गवर्नेंस में बदलने वाला है। मोदी नहीं मोबाइल गवर्नेंस में बदल जाएगा। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि ई-गवर्नेंस, ईजी और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। भविष्य के लिए जरूरी है। इससे लोगों को तमाम सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आने वाले समय में बच्चों की किताब का बोझ में भी यही खत्म कर देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जो भी विरासत में मिला है उसके साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़ना होगा। देश में 25-30 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, यह काफी बड़ी संख्या है। लेकिन इससे वंचित लोग भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब डिजिटल इंडिया को वहां ले जाना है जहां के लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है।

आगे जल्द ही बैंक भी पेपरलेस हो जाएंगे। सब कारोबार तकनीक पर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी से इसकी आहट हो गई। औद्योगिक क्रांति का लाभ नहीं ले पाए क्योंकि हम गुलाम थे। जब आईटी रिवोल्यूशन आया तब हमें इसका फायदा उठाना है। श्री मोदी ने कहा कि पेट्रोलियम आयात हमारी मजबूरी है। यह समझ से परे है कि दूसरा सबसे बड़ा आयात इलेक्ट्रॉनिक सामानों का है। जब इतनी तरक्की है तो क्या यहां इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं बननी चाहिए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इस ओर बढ़ना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नौजवानों को हर मदद देने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में हम स्टार्टअप के क्षेत्र में जल्द ही दूसरे नंबर पर होंगे। गूगल क्यों भारत में नहीं बना। हम देश के नौजवानों से

शेष पृष्ठ 14 पर

सरकार की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिली 50 हजार करोड़ की मंजूरी

सरकार ने बरसात पर निर्भर क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से 50 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना को सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाएगा लेकिन जहां बरसात आधारित कृषि

व्यवस्था है उसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना पर पांच वर्ष में पचास हजार करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के लिए एक समिति बनाई जाएगी और प्रधानमंत्री उसके प्रमुख होंगे। इसके अलावा राज्यों की कार्यकारिणी समिति होगी जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की निगरानी राज्य स्तर पर भी की जाएगी। इस योजना के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का प्रारूप जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि हर राज्य में सिंचाई कमेटी बनेगी जो कि जिला स्तर पर सिंचाई योजना की रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके लिए कमिटी भी गठित कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1000 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत सिंचाई जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने व काम करने की प्रक्रिया में राज्यों को

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मुख्य बातें

- योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति करेगी।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन संसाधनों के आवंटन, अंतर मंत्रालयी समन्वय, निगरानी और प्रदर्शन के आकलन के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) गठित की जाएगी।
- राज्य स्तर पर कार्यान्वयन संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति (एसएलएससी) द्वारा किया जाएगा।
- इस समिति के पास परियोजना को मंजूरी देने और योजना की प्रगति की निगरानी करने का पूरा अधिकार होगा। कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति भी होगी।
- योजना के तहत कृषि-जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तरीय योजनाएं बनायी जाएंगी।
- देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है। योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना है ताकि 'हर बूंद अधिक फसल' ली जा सके।
- इस योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इसके तहत हर खेत तक सिंचाई जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने व उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक स्वायतत्ता व धन के इस्तेमाल की लचीली सुविधा दी गयी है।
- इस योजना में केंद्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।

स्वतंत्रता व धन के इस्तेमाल की सुविधा दी गई है। गौरतलब है कि देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टयर कृषि योग्य भूमि में से 65 फीसद में सिंचाई की सुविधा नहीं है। इस तरह से इस योजना का महत्व और बढ़ जाता है। योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक सिंचाई जल पहुंचाना है। किसानों को सिंचाई से संबंधित सुविधा मुहैया कराना है जिससे हमारे देश का किसान और तरक्की करे।

कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने कृषि उत्पादों के लिए देशभर में एक समान बाजार उपलब्ध कराने के लिए कॉमन नेशनल मार्केट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए कॉमन नेशनल मार्केट का हिस्सा बनने के लिए राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना होगा। केंद्र सरकार के इस कदम से कॉमन नेशनल मार्केट में अब 500 मंडिया एक साथ जुड़ सकेंगी। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट का खाका तैयार होगा। ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए किसान सीधे अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकेंगे।■

पृष्ठ 12 का शेष...

आह्वान है कि वे भारत में ऐसी योजना बनाएं। 'मेक इन इंडिया' के साथ 'डिजाइन इन इंडिया' भी जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में रक्तविहीन युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में मानव जाति को सुख चौन की जिंदगी देने के लिए भारत आगे आ सकता है। रक्तविहीन युद्ध यानी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत के नौजवान कोई तकनीक दे सकते हैं। क्या यहां का जवान दुनिया को विश्वास दिला सकता है। इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। ऐसे में मानव जाति के सुख के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। आज हजारों मील दूर बैठा बच्चा भी कंप्यूटर की मदद से मुसीबत बन सकता है। जरूरी है कि ऐसी व्यवस्थाओं को बनाया जाए कि दुनिया सुरक्षित महसूस करे। इसमें भी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। भविष्य में तमाम डिजिटल लॉकर मिलेंगे। हाई स्पीड डिजिटल हाईवे की अब जरूरत है।

मैं ऐसा सपना देखता हूं कि भ्रष्टाचार पर रोक के लिए डिजिटल माध्यम जरूरी है। ऐसा कोयला खदानों की नीलामी में किया गया।

गौरतलब है कि कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने गांवों में डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में काम कर रही महिलाओं को लैपटॉप और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनावरण किया और डिजिटल भारत से संबंधित नीति दस्तावेजों को जारी किया। श्री मोदी ने डिजिटल इंडिया साप्ताहिक पत्रिका को भी लॉन्च किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री जे.पी. नड्डा, श्री थावर चंद गहलोत, श्री जुआल ओराम तथा श्रीमती निर्मला सीतारमण उपस्थित थीं। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री साइरस मिस्त्री, विप्रो के प्रमुख श्री अजीम प्रेमजी, एयरटेल के चेयरमैन श्री सुनील मित्तल समेत कई बड़े उद्योगपतियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में 400 से भी अधिक प्रमुख उद्योगपति और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ■

केंद्र सरकार ने देश में छह नये आईआईएम स्थापित करने की मंजूरी दी

एमबीए में दाखिला चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने देश में छह नये आईआईएम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो आगामी शैक्षणिक सत्र से ही कोर्स पेश करेंगे। नये आईआईएम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, बिहार के बोध गया, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, महाराष्ट्र के नागपुर, ओडिशा के संभलपुर और पंजाब के अमृतसर में स्थापित होंगे। प्रत्येक संस्थान आईआईएम के प्रमुख कार्यक्रम स्नातकोत्तर कोर्स में 140 छात्रों का दाखिला लेंगे। इनके लिए कैट परीक्षा के तहत दाखिला लिया जायेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी उम्मीद है कि सात वर्ष पूरे होते-होते छात्रों की संख्या बढ़ कर 560 तक हो जायेगी। पिछले वर्ष जुलाई में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने पांच नये आईआईएम स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुरूप आंध्र प्रदेश के लिए भी एक आईआईएम का प्रस्ताव था। कैबिनेट ने पश्चिम ओडिशा के लोगों की पुरानी मांग को भी पूरा करने का निर्णय किया जिसमें संभलपुर में आईआईएम स्थापित करने की बात कही गई थी। पहले के प्रस्ताव के तहत परिसर राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया जाना था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले ही यह तय किया है कि वर्तमान आईआईएम, नये संस्थानों का मार्गदर्शन करेंगे। अभी देश में 13 आईआईएम हैं। ■

वैचारिकी : पिछले अंक का शेष

भारतीय जनसंघ ही क्यों ?

– डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी

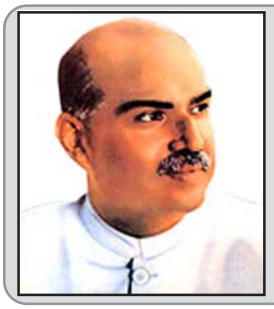

21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली में भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस प्रथम अधिवेशन के अवसर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय जनसंघ की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि विरोधी दल के रूप में वे अविवेकपूर्ण विरोध के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि ऐसे दृष्टिकोण रखने के पक्षधर हैं, जो प्रजातांत्रिक विकास में सहयोग कर सके। ऐसे दूरदर्शी अभिभाषण का द्वितीय भाग हम सुधी पाठकों के लिए यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :-

आर्थिक नीति

आज भारत के सामने सबसे प्रमुख समस्या जनता की गिरती हुई आर्थिक स्थिति है। जनसंघ अस्त्र-वस्त्र की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के प्रयत्नों पर अधिक बल देता है। इसका संबंध उन्नत कृषि एवं व्यापक भूमि सुधार की योजनाओं से होने के कारण हमारा दल इस सम्बंध में प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। हम समझते हैं कि यह सरल कार्य नहीं है और यह तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि करोड़ों प्राथमिक उत्पादकों के उत्साह को जागृत न किया जाये। हम बड़े और छोटे सभी प्रकार के उद्योगों के विकास की सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता का भी अनुभव करते हैं। बढ़ती हुई बेकारी को इसके बिना रोका जा सकता। हमारा ध्येय राष्ट्र के लिए एक सुनिश्चित एवं विकेन्द्रित आर्थिक योजना का निर्माण करना है। जनसाधारण के जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए तथा बड़े उद्योगों के विकास से उत्पन्न बुराइयों के परिणामों से बचने के लिए सर्वोदय योजना की बहुत-सी बातों का भलीभांति उपयोग किया जा सकता है। हम आर्थिक शक्ति के एक छोटे से वर्ग के हाथों में अथवा केन्द्रीयकरण के विरूद्ध हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को हम मान्य करते हैं तथा राष्ट्रों के हितों के अधीन हमें व्यक्तिगत साहस को भी अवसर प्रदान करना है। जनहित में आवश्यक होने पर ही राष्ट्रीयकरण अथवा समय नैपुण्य एवं सार्वजनिक हित का अवश्य ध्यान रखा जाएगा। जनसंघ का उद्देश्य क्रम वर्द्धमान विनियन्त्रण है।

सामाजिक एवं आर्थिक शोषण को रोका जाना चाहिए। वितरण उचित एवं समान होना चाहिए तथा एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिसमें सब लोग मिलकर अधिक उत्पादन कर सकें। विस्थापितों को बसाने की व्यवस्था करना एक भारी समस्या है जिसके लिए अभूतपूर्व सामाजिक एवं आर्थिक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। इसे पूर्ण शक्ति एवं उत्साह के साथ सुलझाना पड़ेगा।

विदेश नीति

विदेश नीति के सम्बन्ध में जनसंघ का मत है कि इसे अधिक यथार्थवादी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रथम विचार यह रखा जाए कि देश के हितों की वृद्धि हो और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सद्भावना की रक्षा हो। हम जनतंत्र और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में विश्वास व्यक्त करते हैं और हम हर प्रकार के अधिनायकवाद के विरुद्ध हैं। हमें यह मानना होगा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी नीति एवं जीवन का दृष्टिकोण अपनी परम्पराओं एवं प्रकृति के अनुरूप निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ''जीओ और जीने दो'' का सिद्धान्त ही भारत का विश्व को सन्देश रहा है। जब तक भारत की अपनी जीवन पद्धति के निर्णय के अधिकार पर कोई आघात नहीं होता तब तक हमें कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम दूसरे देशों के साथ मित्रभाव क्यों न बनाएं रखें। भारत के ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने से हमें बहुत कम लाभ हुआ है। इसके विपरीत हमें भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में अनुभव हुआ है। कि सम्भवत: यह हमारी सरकार के गलत प्रचार के कारण रहा हो । जनसंघ को ब्रिटेन के निवासियों से कोई शिकायत नहीं है। यदि भारत राष्ट्रमण्डल से बाहर भी आया तो भी बरतानिया और अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रति मित्रता के सम्बन्ध बने रह सकतें हैं यदि वे भी भारत के प्रति ऐसा ही व्यवहार रखें।

पाकिस्तान

पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारा यह निश्चित मत है कि भारत का विभाजन स्वीकार करना एक भारी भूल थी। इस विभाजन से कोई लाभ नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की हमारी आर्थिक, राजनीतिक अथवा सांप्रदायिक समस्या के हल करने में सहायता मिली है। अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार पाकिस्तान में हुआ है और आज भी हो रहा है वह सिद्ध करता है कि

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के निमित्त दिए गए आश्वासन भंग कर दिए गए हैं। अखण्ड भारत में हमारी श्रद्धा है।

हमारी मनोकामना है कि दोनों देशों के लोगों की इस अनुभूति के आधार पर कि भारत के संयुक्त होने से ही जन-साधारण का लाभ है और तभी यह देश शांति एवं स्वातंत्र्य का दृढ़ स्तम्भ बन सकता है, यह कार्य शांतिपूर्ण मार्गों से सम्पन्न हो जाए। जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है हम चाहेंगे कि उसके साथ प्रतियोगी सहकारिता की नीति का प्रयोग किया जाए। कांग्रेसी सरकार द्वारा अपनाई हुई आज की तुष्टिकरण नीति ने भारत को दुर्बल बनाया है तथा उसके मान और सम्मान को धक्का पहुंचाया है। इस घुटनाटेक नीति ने पाकिस्तान को सबल और मुंहजोर बना दिया है। पूर्वी बंगाल में अभी भी एक करोड़ से अधिक अल्पसंख्यक जन हैं तथा पश्चिमी पाकिस्तान में थोड़े से शेष हैं। सरकार उनकी सुरक्षा में असफल रही है यद्यपि इस सम्बन्ध में बार बार उसने आश्वासन दिए हैं। यह तर्क माना नहीं जा सकता कि वह दूसरे देश के नागरिक हैं। उन्होंने कभी विभाजित भारत की मांग नहीं की बल्कि उन्हें वचन और आश्वासन दिए गए जिनकी आज खुली अवहेलना की जा रही है।

यह है ऐसा पाप कि जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भारत में विस्थापितों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी हुई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति का प्रश्न भी पड़ा है जिसका सम्मानपूर्वक हल होना चाहिए। परन्तु कांग्रेस सरकार इसे योजनाबद्ध ढंग से टालती जा रही है। हमें इस पर विशेष बल देना है। हमारा इन समस्याओं की ओर देखने का दृष्टिकोण लेशमात्र भी साम्प्रदायिक नहीं हैं। यह प्रमुखतया राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं जिनको दोनों देशों को सीधे और सही रूप से हल करना चाहिये। ...क्रमशः

भाजपा सांसद दिलीप सिंह भूरिया का देहावसान

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ क्षेत्र से सांसद श्री दिलीप सिंह भूरिया का 24 जून को गुड़गांव के एक अस्पताल में संक्षिप्त बीमारी के बाद देहावसान हो गया। वह 71 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो पुत्र एवं चार पुत्रियां हैं।

श्री भूरिया का जन्म 19 जून 1944 को हुआ था और वह सबसे पहले 1972 में कांग्रेस टिकट पर पेटलावद सीट से विधायक चुने गए थे। लोकसभा के लिए वह पहली बार 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। वह झाबुआ से 1996 तक लगातार पांच बार चुने जाते रहे। श्री भूरिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने 1998 के संसदीय चुनाव में भूरिया को झाबुआ सीट से टिकट दिया, लेकिन वह कांग्रेस के श्री कांतिलाल भूरिया से चुनाव हार गए। लेकिन 2014 का चुनाव जीतकर वह एक बार फिर संसद पहुंचे थे।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री दिलीप सिंह भूरिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके निधन से पार्टी ने एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता खो दिया जिन्होंने जनजातियों के लिए व्यापक कार्य किया था। श्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि दिलीप सिंह भूरिया के निधन से हमने एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता खो दिया, जिन्होंने जनजाती समुदाय के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना भूरिया के परिवार वालों के साथ है। भगवान दिवंगत नेता की आत्मा को शांति दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूरिया का मध्य प्रदेश और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों का विधायी अनुभव रहा है जो कि उनकी प्रमुख पूंजी है। श्री भूरिया का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव माछिला, जिला झाबुआ में 25 जून को हुआ। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रभात झा, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम, श्री थावरचंद गहलौत और श्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित थे। ■

भाजपा अध्यक्ष का शोक संदेश

श्री दिलीप सिंह भूरिया सदैव वनवासियों, गरीबों और किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए संघर्ष किया। वे मध्य प्रदेश से विधायक और पांच बार सांसद निर्वाचित हुए। उनके निधन से देश ने एक जनसेवक को खो दिया है। जिसकी भरपाई होना बेहद मुश्किल है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ■

सामाजिक-आर्थिक तथा जाति जनगणना का संदेश

✍ अरुण जेटली

दिनांक 5 जुलाई 2015 को सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसीईसीसी) की जारी की गयी विज्ञप्ति भारत के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए रणनीति पर चिंतन करने का एक अवसर प्रदान करती है। वंचितों के आर्थिक जीवन में सुधार करने की दिशा में हालांकि उल्लेखनीय प्रगति हुई है परन्तु अभी भी बड़े पैमाने पर यह चिंता का विषय बना हुआ है। उदहारण के तौर पर, 30 प्रतिशत परिवार एसीसीसी के गरीब और वंचित वर्ग को पारिभाषित करनेवाले सात पैमानों में से बस दो पर खड़े उतरते हैं और 49 प्रतिशत परिवार बस एक पर। इस स्थिति में सुधार लाना इस सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकता है।

लेकिन हम कैसे सबसे प्रभावी ढंग से और जल्द-से-जल्द अपने इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं? सबसे अच्छा गरीबी विरोधी उपाय एक स्थायी, औपचारिक क्षेत्र और अच्छी तरह से भुगतान वाला रोजगार उपलब्ध कराना है। एसीईसीसी इस निष्कर्ष को दर्शाता है कि वंचितों के पहचान के सात आधारों में से जो इस जर्जर अवस्था का सबसे बड़ा कारक है, वह है भूमिहीन परिवार जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक तथा सामयिक मजदूरी से अर्जित करते हैं।

हमें इस समस्या को खत्म करने के लिए 8-10 प्रतिशत की तेजी से आर्थिक विकास दर हासिल करना है ताकि जल्द-से-जल्द सभी सभी भारतीयों के लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकें। यही कारण है कि सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है।

वंचितों के आर्थिक जीवन में सुधार करने की दिशा में हालांकि उल्लेखनीय प्रगति हुई है परन्तु अभी भी बड़े पैमाने पर यह चिंता का विषय बना हुआ है। उदहारण के तौर पर, 30 प्रतिशत परिवार एसीसीसी के गरीब और वंचित वर्ग को पारिभाषित करनेवाले सात पैमानों में से बस दो पर खड़े उतरते हैं और 49 प्रतिशत परिवार बस एक पर। इस स्थिति में सुधार लाना इस सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकता है।

सड़क, रेलवे, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है। (छत्तीसगढ़ के ग्रामीक इलाकों में से केवल एक चौथाई क्षेत्र में अभी मोबाइल सेवा उपलब्ध है)

सरकार अधिक से अधिक निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी लागू करना, एक साझा बाजार बनाना, भूमि कानून में सुधार, व्यापार कर की लागत कम करना और अनवरोधित व ठप परियोजनाओं की स्थिति में सुधार जैसे कोशिश कर रही है।

ताजा आंकड़े यह सुझाव देते हैं कि निवेश चक्र धीरे-धीरे आगे की ओर घूम रहा है और रुके परियोजनाओं को एक तेज गति से शुरू किया जा रहा। जीएसटी पासिंग और भूमि कानून में सुधार इस निवेश में बदलाव को गति देगा।

हमें लक्षित योजनाओं और नीतियों की जरूरत है ताकि ना केवल गरीबी उन्मूलन के लिए विकास के प्रभाव को और अधिक प्रभावी बनाना है वरन उन लोगों की भी सहायता करनी है जो अभी तक विकास के मुख्यधारा से छूटे हुए हैं। सरकार सब्सिडी देकर गरीबों के मदद कर रही है लेकिन यह लाभ सही तबके को पहुँच नहीं रहा है और इसमें काफी त्रुटियाँ हैं। अगर हम सरकार के जेएम यानी जन-धन आधार और मोबाइल योजनाओं के दृष्टिकोण को समझें तो हम यह एहसास कर सकते हैं कि पैसा सीधे और अधिक तेजी से गरीबों की जेब तक पंहुच रहा है और इस प्राप्त बचत से हम गरीबों के लिए और अधिक मात्रा में हम उनके लिए पैसा लगा सकते हैं।

रसोई गैस में डीबीटी योजना के तहत अनुभव बहुत उत्साहजनक हैय मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसंधान से पता चलता है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना से इस वर्ष 12,700 करोड़ रुपये (25 प्रतिशत) बचाया जा सकेगा। अगर हम इसकी रूपरेखा और इसके क्रियान्वयन में जरा सी सावधानी बरतें तो हम इस योजना का विस्तार अन्य वस्तुओं के लिए कर सकते हैं ताकि गरीब वर्ग को उपने उत्थान के लिए और अधिक पैसा मिले।

इसके अलावा, हमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों से गरीबों की रक्षा कर उनकी मदद करनी चाहिए। हमें किसानों के लिए मौसम और अन्य विपत्तिपूर्ण जोखिम से उनकी रक्षा के लिए तथा अधिक प्रभावी फसल बीमा प्रदान करने

शेष पृष्ठ 23 पर

बिहार

जंगलराज बनाम विकास-राज

संजीव कुमार सिन्हा

सेमीफाइनल राजग जीत गया। बिहार विधान परिषद् का चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था। भाजपा-लोजपा-रालोसपा के राजग गठबंधन ने जद(यू)-राजद-कांग्रेस के 'महागठबंधन' को धूल चटा दिया। हाल ही में बिहार विधान परिषद् के स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में राजग ने शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा के सर्वाधिक प्रत्याशी विजयी हुए। 18 सीटों पर चुनाव लड़ी भाजपा ने 11 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं जदयू को महज पांच, राजद को चार और कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा।

अब फाइनल दो महीने बाद होने हैं। सितंबर-अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी माहौल गरमाने लगा है। सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। बिहार के दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए इस चुनाव के खास मायने हैं। भाजपा-लोजपा-रालोसपा और जद(यू)-राजद-कांग्रेस-राकांपा के बीच मुकाबला है। वाम दलों ने जनता परिवार के साथ गठबंधन की किसी संभावना को खारिज करते हुए स्वतंत्र समूह के तौर पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। वाम मोर्चे में माकपा, भाकपा के अलावा भाकपा माले, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एसयूसीआई (सी) और आरएसपी शामिल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी 18 विधायक के साथ हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा बनाकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को जी भर कर कोस रहे हैं। लालू प्रसाद के पूर्व सहयोगी सांसद पप्पू यादव अब जन अधिकार पार्टी बनाकर कोशी क्षेत्र में सक्रिय है। लालू प्रसाद के साले एवं पूर्व सांसद साधु यादव ने गरीब जनता दल (सेक्यूलर) के नाम से नई पार्टी बना ली है। ये सभी जद(यू) और राजद से अलग हुए हैं, इसलिए जाहिर है इससे जद(यू)-राजद की स्थिति कमजोर होगी।

फिर से राज्य को जातिवाद के दलदल में धकेलने का षड्यंत्र हो रहा है। जद(यू)-राजद जहां खास जातियों के सहारे चुनाव मैदान में खड़ी है वहीं भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। विकास की रफ्तार में देश में बिहार काफी पिछड़ गया है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरे, शिक्षा-स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, कल-कारखाने लगे, इसके लिए जरूरी है कि बिहार की सत्ता जातिवादी ताकतों के हाथों में न होकर विकास की राजनीति करनेवालों के पास हो। भाजपा विकास की राजनीति करती है। पार्टी का सिद्धांत है 'सबका साथ-सबका विकास।'

बिहार चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी चुनाव-प्रचार शुरू हो गया है। फेसबुक, ट्विटर और वाट्सएप पर संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा ने नारा दिया है, 'लालू-नीतीश यानी विनाश, भाजपा मतलब विकास'। जदयू का नारा है 'बढ़ चला बिहार' तो भाजपा कह रही है "अपराध, भ्रष्टाचार और अहंकार, क्या इसी गठबंधन से बढ़ेगा बिहार।" राजद प्रमुख लालू प्रसाद प्रमंडलवार कार्यकर्ताओं की मंशा जानने में जुटे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी मिस्ड कॉल के जरिए सदस्यता अभियान चला रही है।

चुनाव-प्रचार को लेकर भाजपा ने सघन रणनीति बनाई है। 25 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मुजफ्फरपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव में मिशन 185 प्लस को पूरा करने के लिए पार्टी 100 दिनों में पूरे राज्य में एक लाख सभाएं करेगी। इसके लिए 160 रथ तैयार होंगे। पार्टी ने योजना बनाई है कि एक दिन में पार्टी कम से कम 800 गांवों तक पहुंचेगी। यह रथ राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा। रथ पूरी तरह हाईटेक होगा और इसमें ऑडियो-वीडियो दोनों सुविधाएं होंगी। गौरतलब है कि भाजपा बिहार की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो सभी 62 हजार बूथों तक पहुंच चुकी है। पार्टी के प्रत्येक बूथ पर 21-21 कार्यकर्ता तैयार हैं। पार्टी विरोधियों को चुनौती देने के लिए कमर कस चुकी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'हर घर दस्तक' अभियान की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 10 लाख कार्यकर्ताओं का एक करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस अभियान के दौरान वे जनता को खूब भरमा रहे हैं। एक सभा में उन्होंने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें दोबारा सत्ता

दिलाई तो पूरे राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस पर भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सटीक टिप्पणी की, ''यह वादा करके नीतीश कुमार ड्रामा कर रहे हैं। शराबबंदी लागू ही करनी है तो तीन महीने का इंतजार वह क्यों कर रहे हैं? अगर उनमें दम है तो अभी इसे लागू क्यों नहीं करते। यह तो चंद मिनटों में लागू हो जाएगी। भाजपा इस कदम का पूरा समर्थन करेगी।'' विदित हो कि गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पूरी शराबबंदी लागू है।

राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पप्पू यादव अपने पूर्व नेता लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोल रहे हैं। लालू प्रसाद द्वारा उन्हें 'मीरजाफर और जयचंद' कहकर पुकारने पर उन्हें 'दुर्योधन और कंस' बताते हुए पलटवार किया।

लालू-राबड़ी के समय बिहार में जंगलराज था। भय और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त थे। ऐसे में जदयू-भाजपा गठबंधन ने जंगलराज से बिहार को मुक्ति दिलाई। बिहार में विकास हुआ। एनडीए के आठ साल के शासन के दौरान सुशासन कायम हुआ तब जदयू के भाजपा साथ थी। भाजपा के कोटे के मंत्रियों के विभागों ने एनडीए सरकार के दौरान बिहार में सबसे ज्यादा काम किया। 17 सालों तक यह गठबंधन चला। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण इसे तोड़ दिया। उन्होंने जनादेश का अपमान कर लालू प्रसाद से हाथ मिलाया और बिहार में विकास का बंटाधार कर दिया। बिहार में कानून- व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा-स्वास्थ्य का बुरा हाल है, बिजली की किल्लत है, ऐसे अनेक समस्याओं से राज्य ग्रसित है।

अनेक वर्ष के संघर्ष के पश्चात् बिहार में जातिवादी ताकतों की करारी शिकस्त हुई थी। अब फिर से राज्य को जातिवाद के दलदल में धकेलने का षड्यंत्र हो रहा है। जद(यू)-राजद जहां खास जातियों के सहारे चुनाव मैदान में खड़ी है वहीं भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। विकास की रफ्तार में देश में बिहार काफी पिछड़ गया है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरे, शिक्षा-स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, कल-कारखाने लगे, इसके लिए जरूरी है कि बिहार की सत्ता जातिवादी ताकतों के हाथों में न होकर विकास की राजनीति करनेवालों के पास हो।

भाजपा विकास की राजनीति करती है। पार्टी का सिद्धांत है 'सबका साथ-सबका विकास।' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। भाजपा शासित 13 राज्यों में विकास की बयार बह रही है।

बिहार विधान परिषद् चुनाव में यह स्पष्ट हो गया कि जद(यू)-राजद का गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है और दोनों दलों के कार्यकर्ता एक साथ काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं। मतदाताओं ने भी अपना मंतव्य जाहिर कर दिया है। वे जातिवादी राजनीति को नकार रहे हैं और विकास की राजनीति में भरोसा जता रहे हैं। ■

विधान परिषद् चुनाव में खिला कमल

बिहार विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे विधान परिषद् के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने जद (एकी), राजद, कांग्रेस और राकांपा के महागठबंधन को करारी शिकस्त दी है। स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद् की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में राजग ने 12 सीटें जीती हैं। वहीं सत्तारूढ़ महागठबंधन को 10 सीटें मिली हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है।

विधान परिषद् चुनाव में राजग के प्रमुख दल भाजपा ने 18, लोजपा ने चार और रालोसपा ने दो सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा ने सर्वाधिक 11 सीटों पर दर्ज की है। एक सीट भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने जीती है। लोजपा को एक सीट मिली है। वहीं महागठबंधन में शामिल जद (एकी) और राजद ने 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जद (एकी) को पांच और राजद को चार सीटें मिली हैं। तीन सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को एक सीट मिली है। ■

आपातकाल के संघर्ष को याद रखना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 25 जून 2015 को दिल्ली के मावलंकर हॉल में आपातकाल के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी 'लोकतंत्र का काला दिवस' को सम्बोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान द्वारा किया गया था।

उन्होंने अपने उद्‌बोधन की शुरुआत करते हुये सर्वप्रथम उन लोगों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किया जिन्होंने आपातकाल की मानसिकता के खिलाफ संघर्ष किया था और 1975-1977 के दौरान यातनाएं झेलीं थी। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने उस नाजुक मोड़ पर देश के लोकतंत्र को न केवल बचाया वरन लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया तथा यह सुनिश्चित किया कि सालों साल तक किसी की हिम्मत न हो सके फिर से ऐसा दुस्साहस करने की। श्री शाह ने कहा की उनका बलिदान आनेवाली कई पीढ़ियों के लिए वंदनीय है।

श्री शाह ने सम्मलेन में द्वारिका में श्रीकृष्ण की शासन प्रणाली व मगध साम्राज्य के शासन व्यवस्था की चर्चा करते हुये कहा कि विश्व में सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की शुरुआत भारत से ही हुई थी। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे परिवर्तनशील लोकतंत्र है।

श्री शाह ने कहा कि 25 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक का समय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। आपातकाल के संघर्ष को याद रखना नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। आपातकाल ना तो अध्यादेशों से आता है और ना ही अध्यादेशों को लाने के विचारों से आता है। आपातकाल कुत्सित मानसिकता से आता है जब शासनतंत्र दूसरे के विचारों को सुनना ही नहीं चाहती, स्वतंत्र विचारों का दमन करने लगती है और लोकतंत्र के चारों स्तम्भों को सीखचों के पीछे डाल देती है तो यह तानाशाही की ही मानसिकता होती है।

श्री शाह ने आपातकाल की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुये कहा कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कांग्रेस में सिंडिकेट युग की शुरुआत हो गई और अंततः कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उस वक्त कांग्रेस के असंतुष्टों को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिये थी, उन्हें पार्टी के अंदर रहते हुये संघर्ष करना चाहिए था ताकि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी रहती। उन लोगों के पार्टी छोड़ने से सत्ता और संगठन की सारी बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई और वह निरंकुश और तानाशाह हो गई और उसका ही परिणाम था कि देश को आपातकाल जैसी वीभत्स परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

आपातकाल ना तो अध्यादेशों से आता है और ना ही अध्यादेशों को लाने के विचारों से आता है, आपातकाल कुत्सित मानसिकता

श्री शाह ने कहा कि उस वक्त चापलूस और चाटुकारों का बोलबाला था, मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई थी, शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। आपातकाल देश की शान्ति, सुरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए नहीं लाया गया था जैसा कि प्रचारित किया गया, वरन इसे अपनी सत्ता को बचाने के लिये लाया गया जो कि निश्चित रूप से एक असंवैधानिक कदम था।

उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुये कहा कि पटना में देवकांत बरूआ की गाड़ी ने एक 9 वर्ष के बच्चे को कुचल दिया। पूरा काफिला उस बच्चे के ऊपर से गुजर गया पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में अगले दिन प्रकाशित हुई तो पूरे देश में आक्रोश के लहर दौड़ गई।

श्री शाह ने सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुये कहा कि जयप्रकाश जी के आंदोलन ने पूरे देश में क्रांति की एक नई अलख जगाई थी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आहवान किया था।

3 जनवरी 1975 को तत्कालीन रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या कर दी गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर इसे असंवैधानिक करार कर दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर हालांकि रोक लगा दी और एक ऐसा फैसला दिया, जिससे इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना बिलकुल असंवैधानिक हो गया। इंदिरा गांधी और उनके पूरे शासन तंत्र ने यह प्रचारित करने की पूरी कोशिश की कि यह इंदिरा गांधी की जीत हो गयी है। इतने अपमानित तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाई गई कि पूरा लोकतंत्र शर्मसार हो गया और अंतत: 25 जून की आधी रात को पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और फिर शुरू हुआ दमन चक्र। विरोधी पक्ष के लोग जो जहाँ थे उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तब कैबिनेट को पता चला कि देश में आपातकाल लगा दिया गया है। एक आंकड़े के अनुसार सुबह 6 बजे तक लगभग 9 हजार से ज्यादा लोगों को एक रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री आडवाणी जी को बंगलोर में ही गिरफ्तार कर लिया गया।

क्यों कांग्रेस पार्टी को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जासूसी करानी पड़ी, क्यों सरदार पटेल को भारत रत्न देने में सालों लग जाते हैं, संविधान निर्माता बाबासाहब अंबेडकर के चित्र को संसद में लगाने में वर्षों लग जाते हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेहरू जी के जन्मशती मनाने के लिए समिति का तुरंत गठन कर देती है और लौह पुरुष सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का कार्य गुजरात में शुरू करती है।

सरकार ने अध्यादेश पर अध्यादेश जारी करके न्यायपालिका को मजबूर कर दिया, मीडिया पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और मीसा को और अधिक मजबूत बना दिया ताकि लोगों की आवाजें पूर्णतया खामोश हो जाये। कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र के चारों स्तम्भों को कुचलने की भरपूर कोशिश की गई। लगभग 1 लाख 40 हजार लोगों को अमानवीय तरीके से लगातार 19 महीनों तक जेल के सलाखों के पीछे रखा गया और उन्हें कठोरतम यातनाएं दी गई लेकिन इतना संघर्ष और दमन होने के बावजूद न कोई टूटा और न ही कोई झुका। वास्तव में भारत के मिटटी में लोकतंत्र की खुशबू बहुत गहरी है।

इन संघर्षो के परिणामस्वरूप 1977 में जनसंघ ने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए जनता पार्टी में अपना पूर्ण विलय कर दिया। श्री मोरारजी के नेतृत्व में सरकार बनते ही आपातकाल के दौरान जारी किये गए सारे अध्यादेशों को निरस्त कर दिया गया और संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सके।

आज जो हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, जो मीडिया की स्वतंत्रता बची है और लोगों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता व्यापक हुई है वह आपातकाल के दौरान उन हजारों लोगों के बलिदान के फलस्वरूप ही संभव हो पाया है।

श्री शाह ने संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि क्यों कांग्रेस पार्टी को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जासूसी करानी पड़ी, क्यों सरदार पटेल को भारत रत्न देने में सालों लग जाते हैं, संविधान निर्माता बाबासाहब अंबेडकर के चित्र को संसद में लगाने में वर्षो लग जाते हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेहरू जी के जन्मशती मनाने के लिए समिति का तुरंत गठन कर देती है और लौह पुरुष सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का कार्य गुजरात में शुरू करती है।

कांग्रेस के आतंरिक लोकतंत्र पर

शेष पृष्ठ 23 पर

अमरुत, स्मार्ट सिटी मिशन और सभी के लिए मकान (शहरी) योजना का शुभारंभ
शहरों की बदलेगी तस्वीर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को शहरी भारत की तस्वीर बदलने के उद्देश्य से तीन बड़ी योजनाएं शुरू कीं। प्रधानमंत्री ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट सिटी मिशन, पुनरुद्धार एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमरुत) और सभी के लिए आवास मिशन का आगाज किया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पांच साल में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी, जबकि अमरुत योजना में 500 शहर विकसित किए जाएंगे। सबके लिए आवास योजना में सात साल में शहरी क्षेत्रों में दो करोड़ घर बनाए जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को शहरों के संतुलित एवं समुचित विकास हेतु तीन बड़ी शहरी योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि निजी प्रॉपर्टी डेवलपर्स को यह फैसला नहीं करना चाहिए कि शहर का विकास कैसे होगा, बल्कि यह फैसला निवासियों और शहर के नेतृत्व को करना चाहिए। श्री मोदी ने पुनरुद्धार एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और सभी के लिए आवास मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि शहरीकरण को एक अवसर और शहरी केंद्रों को विकास के इंजन के तौर पर देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं और इसे मिलकर (केंद्र एवं राज्य) कर सकते है। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हर साल हिंदुस्तान एक छोटे देश को जन्म देता है। अमरुत योजना के तहत 500 शहर विकसित किए जाने हैं। 100 स्मार्ट शहर पांच साल के भीतर विकसित किए किए जाएंगे और सभी के लिए आवास योजना के तहत अगले सात साल में दो करोड़ मकानों का शहरी क्षेत्रों में निर्माण कराना है।

स्मार्ट सिटी का चयन शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा के जरिए होगा जबकि अमरुत के तहत 500 शहरों की पहचान की जा रही है। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी का हवाला देते हुए कहा कि भारत में पहली बार यह चुनौती रखी जा रही है जिसमें भारत के नागरिक अपने शहरों के विकास का दृष्टिकोण तय करने में योगदान दे सकते हैं ।

शहरों के विकास के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि यदि 25-30 वर्ष पहले ऐसा किया गया होता तो आज अच्छे परिणाम मिलते, फिर भी नहीं से देर भली। उन्होंने कहा कि आज स्पष्ट विजन और जन केंद्रित योजनाओं की आवश्कता है। उन्होंने कहा कि देश के श्रेष्ठ व्यवहारों को दोहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में कर वसूली प्रणाली, कर्नाटक में ठोस कचरा प्रबंधन तथा छत्तीसगढ़ में खुले में शौच करने की प्रथा को खत्म करने के प्रयासों की विशेष रूप में चर्चा की।

बढ़ती आबादी की चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरी विकास के लिए संसाधन जुटाने के सभी रास्तों की तलाश की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए मकान उनके जीवन में बदलाव लाता है। इससे गरीब का जीवन बेहतर

होता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास केवल मकान देना नहीं, बल्कि पूरा जीवन जीने के लिए उचित माहौल प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री ने देश में 2 करोड़ आवास इकाइयों की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा करेगा। तब तक सबको मकान देना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरी नियोजन के बारे में समग्र विजन का अभाव है। विस्तार शहर के प्रशासकों द्वारा प्रेरित नहीं है बल्कि प्रोपर्टी डेवलपरों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अमरुत के माध्यम से शहरों को अपने भविष्य के विकास की योजना बनाने का अवसर देना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शहरी और ग्रामीण विकास एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने का एक तरीका यह है कि शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन किया जाए और शोधित जल को सिंचाई के लिए गांवों में भेजा जाए। इसी तरह ठोस कचरा प्रबंधन से कम्पोस्ट खाद तैयार किया जा सकता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में जैव उर्वरक के रूप में काम आ सकता है।

प्रधानमंत्री ने अमरुत तथा स्मार्ट सिटिज के लिए लोगो तथा टैगलाइन और अमरुत, स्मार्ट सिटी मिशन तथा सबके लिए मकान (शहरी) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू, शहरी विकास राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री देवेंद्र फणनविस , हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर तथा जम्मू-कश्मीर के उप-मुख्यमंत्री श्री निर्मल कुमार सिंह उपस्थित थे। ■

पृष्ठ 21 का शेष...

हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि जिस पार्टी का कभी भी आतंरिक लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, जिसकी सोच ही तानाशाही है, जहाँ किसी भी फैसले में आम कार्यकर्ताओं की सुनी ही नहीं जाती उसके हाथ में सबसे बड़े और सबसे मजबूत लोकतंत्र की चाभी कैसे दी जा सकती है। कांग्रेस का पूरा अतीत इस बात की गवाही देता है कि शुरू से लेकर अब तक केवल एक परिवार के हाथ में ही पार्टी की पूरी कुंजी रही है।

उन्होंने सम्मलेन में उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप व्यक्ति को वोट ना दें। देश की जनता का विचार बदलने का वक्त आ गया है। आप पार्टी की विचारधार व विचारों में अपनी आस्था व्यक्त करें, आप एक ऐसी पार्टी को चुनें जहाँ आपकी बातों व हितों को महत्व दिया जाए, जिस पार्टी में आतंरिक लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो देश में कभी भी आपातकाल नहीं आयेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1650 पार्टियों में दो-तीन पार्टियां ही ऐसी हैं जिसमे आतंरिक लोकतंत्र है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को उन्हीं दिशाओं में ले जाने का सतत प्रयास करेगी जिसका सपना स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने की थी और जिसकी रक्षा के लिए हजारों लोगों ने संघर्ष किया और यातनाएं झेलीं।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार के छपरा में जन आंदोलन के नायक स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में स्मारक बनाये जाने की घोषणा पर अपना आभार व्यक्त करते हुये कहा कि हम लोग सदैव जय प्रकाश जी के जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे एवं श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान के निदेशक डॉ. अनिर्बन गांगुली सहित अनेक विशिष्टजनों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

पृष्ठ 17 का शेष...

के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की जरूरत है। दूसरों के लिए विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में हमें बुढ़ापा, बीमारी और दीर्घायु के खिलाफ सामाजिक बीमा की जरूरत है। बजट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना सहित बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा हुई है। हम इन योजनाओं को मजबूत बनाने का इरादा रखते हैं ताकि प्रोत्साहन दिया जा सके।

विकास या पुनर्वितरण? नीतिगत सुधार या लक्षित गरीबी विरोधी योजनाएँ? हम विश्वास करते हैं कि यह एक निराधार चुनाव है। दोनों जरूरी हैं। विकास और आर्थिक सुधार लक्षित योजनाओं द्वारा गरीबों की मदद करते हैं। एसीईसीसी से हमें यही सन्देश मिलता है। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं।)

देश में दूसरी कृषि क्रांति की आवश्यकता : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी ने 28 जून को हजारीबाग के बरही में एक हजार एकड़ भूमि पर बनने वाले भारतीय कृषि शोध संस्थान की आधारशिला रखने के बाद कहा कि अब देश में बिना किसी बिलंब के दूसरी कृषि क्रांति की आवश्यकता है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात पर दु:ख प्रकट किया कि आजादी के 68 सालों बाद भी कृषि को वह महत्व नही मिल सका है जो उसे मिलना चाहिए था। लिहाजा, अब देश में दूसरी हरित क्रांति होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे ज्ञान और सूचनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस दूसरी कृषि क्रांति के प्रारंभ होने की संभावना देश के पूर्वी क्षेत्र से है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है।

उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास की योजना विशेष रूप से बना रही है और यहां कृषि के समुचित विकास को दृष्टिगत रखकर ही देश का यह दूसरा बड़ा कृषि शोध संस्थान बरही में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री ने दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए किसानों से देश में दालों का उत्पादन स्तर बढ़ाने का आह्वान किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के नारे 'जय जवान जय किसान' का आह्वान करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक किसान से अपनी भूमि के कुछ भाग में दालों का उत्पादन करने का प्रयास करने के लिए कहा। उन्होंने दाल क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि दालें आम आदमी के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि इनपुट, सिंचाई, मूल्य संवर्धन और बाजार जुड़ावों में पीछे है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने और इसे अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसाधनों के उचित आवंटन और प्रशिक्षण की जरूरत है। यह देखते हुए कि जनसंख्या में वृद्धि

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूर्वी भारत में कृषि के क्षेत्र में नये युग का आरंभ करेगा।
- कृषि को आधुनिक बनाने पर हो रहा काम।
- किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड मिलेगा।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का काम पूरा करेंगे।
- नहर बना कर हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे।
- पशुपालन से किसानों के लाभ के लिए बन रही योजना।
- किसानों को उत्पादित वस्तु के लिए सही बाजार व दाम मिलेगा।
- झारखंड में डेयरी का विकास होगा।
- पशुपालन से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार योजना बना रही है।
- बिहार हर वर्ष 400 करोड़ की मछली दूसरे राज्यों से आयात करता है। वहां मत्स्य उद्योग पर काम नहीं हुआ।

हो रही है और भूमि-जोत खंडित हो रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसानों को अच्छी आय सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी कृषि जलवायु संभागों में उचित अनुसंधान की जरूरत है। यह बेहतर परिणाम सुनिश्चित करेगा, साथ ही साथ, किसानों के बीच इसकी स्वीकार्यता भी बेहतर होगी। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा का प्रसार करने की जरूरत है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार का सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है जिससे मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार का स्रोत उपलब्ध कराया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार में झारखंड में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक जिले को शहद उत्पादक जिले के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी उल्लेख किया। प्रति बूंद अधिक फसल के अपने मंत्र का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई ने उत्पादकता वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने में मदद की है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दूसरे भागों और दुनिया के अन्य देशों में कृषि क्षेत्र में हुए शोधों के मुकाबले अपने क्षेत्र में कृषि संबंधी शोध होने से किसानों को अधिक लाभ और आत्मीयता का बोध होगा। उन्होंने कहा कि देश में किसान सैकड़ों वर्षो से खेती के लिए केवल मानसून पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने अब उन्हें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सिंचाई के आधुनिक साधन उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत देश के जलाशयों का पानी टपक सिंचाई योजना के तहत किसानों के खेतों तक पहुंचाने की योजना है। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत सभी पूर्वी राज्यों में दुधारू पशुओं की अधिक संख्या को देखते हुए केन्द्र सरकार ने झारखंड को भी राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम में शामिल करने का पिछले माह निर्णय किया है।

श्री मोदी ने कहा कि **कृषि के तेजी से विकास के लिए इन इलाकों में स्थित पुराने खाद के कारखानों को पुनर्जीवित करने और नए खाद के कारखाने स्थापित करने का फैसला केन्द्र सरकार ने किया है। इसी योजना के तहत झारखंड के सिंदरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित खाद के पुराने कारखानों को पुनर्जीवित करने का केन्द्र सरकार ने फैसला किया है।** इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी पुराने खाद के कारखानों को पुनर्जीवित करने और नए कारखानों को स्थापित करने की योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि परिवहन लागत बचने से पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के किसानों को सस्ते मूल्य पर यूरिया एवं रासायनिक खाद आसानी से उपलब्ध हो सकेगी जिससे देश में खाद्य उत्पादन तेजी से बढ़ाने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में केन्द्र सरकार की ओर से इस्पात मंत्रालय, झारखंड सरकार और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत राज्य में एक अल्ट्रा मेगा इंटीग्रेटिड स्टील कारखाने का निर्माण होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पुराने बिहार का गौरव समस्तीपुर का पूसा संस्थान जो दिल्ली चला गया था, उसे प्रधानमंत्री पुरानी धरती पर वापस लाये हैं। झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए एक हजार एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करायी। रघुवर दास की सरकार बनते ही चंद दिनों में जमीन उपलब्ध करा दी गयी। यह केंद्र कृषि के क्षेत्र में वरदान साबित होगा।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि विश्व के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गये हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दिल के एक कोने में हजारीबाग बसता है। प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस संस्थान को स्थापित कर हजारीबाग के लोगों को बड़ी सौगात दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने इस अवसर पर अपनी सरकार के छह माह पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया और दावा किया कि केन्द्र की मोदी सरकार की तरह ही उनकी सरकार के भी पहले छह माह बेदाग और भ्रष्टाचार मुक्त रहे है और इस दौरान किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नही लगे हैं। गौरतलब है कि झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ■

जगन्नाथ राव जोशी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 23 जून 2015 को कर्नाटक के नरगुंड में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और विचारक कर्नाटक केसरी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ राव जोशी के स्मारक का उद्घाटन किया।

उन्होंने विशाल संख्या में स्वर्गीय जोशी जी को श्रद्धांजलि देने आये लोगों को धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत श्री शाह ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुये लोगों से भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री जगन्नाथ राव जोशी जी के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही।

उन्होंने लोगों को याद दिलाते हुये कहा कि आज श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का संकल्प लेकर एक मजबूत भारत की परिकल्पना की थी।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर की एकता और अखंडता के लिये अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने उस वक्त श्री जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा था ''एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान - नहीं चलेगा, नहीं चलेगा''। वह अंत तक अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। देश की एकता, अखंडता और कश्मीर के लिए उनके द्वारा दिये गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

उन्होंने जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज ही हम इन दोनों पुण्यात्माओं का स्मरण कर रहे हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ राव जोशी एक असाधारण राष्ट्रभक्त, लोकप्रिय संघ-प्रचारक और तेजस्वी सांसद थे। श्री शाह ने कहा कि स्वर्गीय जोशी जी ने अपना पूरा जीवन जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए समर्पित कर दिया। वे सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। उन्हें न तो पद की लालसा थी और न ही प्रसिद्धि की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने कर्तव्यनिष्ठा का एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। वे सच्चे अर्थों में कर्नाटक केसरी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा और देश सेवा में अर्पण कर दिया। श्री जोशी जी द्वारा गोवा मुक्ति संग्राम में दिये गये अमूल्य योगदान की चर्चा करते हुये श्री शाह ने कहा कि उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान बड़ी प्रताड़ना झेली और अंतत: गोवा मुक्ति आंदोलन सफल हुआ। उन्होंने कहा कि देश के जनता द्वारा दिया गया सम्मान और महत्व किसी भी सम्मान से बड़ा होता है।

हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिये। उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया। हमें उनके द्वारा स्थापित आदर्श के उच्चतम मापदंडों पर खरा उतरना है। उनके जीवन से हमें सीख लेनी है और उनके विचारों को जन-जन तक पहुँचाना है।

ऐसे ही आदर्श महापुरुषों द्वारा किये गये कार्यों का परिणाम है कि 10 लोगों द्वारा स्थापित की गयी पार्टी के आज 10 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य है। आज भारतीय संस्कृति का गौरव पूरे विश्व में लहरा रहा है। श्री शाह ने कहा कि हम हरेक क्षेत्रों में आज आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ राव जोशी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके विचारों का अपने जीवन में पूरे मनोयोग से पालन करें।

उन्होंने कहा कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्गीय जगन्नाथ राव जोशी के जीवन को स्मरण करने का जो अवसर उपलब्ध कराया है, उसके लिये मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम सभी को उनके द्वारा दिखाये गये मार्गदर्शन में काम करने की जरूरत है।■

पांच राज्यों की 6 विधान सभा सीटों पर उपचुनाव

मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत

केरल में भाजपा के मतों में चार गुणा बढ़ोतरी और त्रिपुरा में कांग्रेस को पछाड़ा

पिछले दिनों देश के पांच राज्यों मध्य प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, मेघालय व तमिलनाडु की 6 विधान सभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए। उपचुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि भाजपा ने न केवल मध्य प्रदेश की अपनी सीट बरकरार रखी है, बल्कि केरल में भाजपा के मतों में लगभग चार गुना की बढ़ोतरी हुई है। त्रिपुरा में भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है और उसने कांग्रेस को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया है। इस उपचुनाव से स्पष्ट है कि भाजपा का देशव्यापी जनाधार और मजबूत हुआ है।

हाल ही में देश के पांच राज्यों की 6 विधान सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित किए गए। इन उपचुनाव के नतीजे प्राय: परंपरागत रूप से सत्ताधारी दलों के पक्ष में गए, लेकिन इन परिणामों के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि भाजपा का देशव्यापी जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा उप चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार श्री चंदर सिंह सिसोदिया विजयी रहे। भाजपा ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। यहां भाजपा के चंदर सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के सुभाष कुमार सोजतिया को 12,945 मतों से पराजित किया।

हालांकि केरल में भाजपा के अनुभवी नेता श्री ओ. राजगोपाल विधानसभा उप-चुनावों में अपने निर्वाचन क्षेत्र अरूविक्कारा से तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन क्षेत्र में पार्टी की मत हिस्सेदारी में 2011 की तुलना में लगभग चार गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन नतीजों से कांग्रेस और वामपंथी दोनों हैरान हैं। गौरतलब है कि श्री राजगोपाल को 2011 विधानसभा उपचुनावों में लगभग 7,000 मतों की तुलना में इस बार 34,145 मत प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस के के.ए. सबरीनाथन ने मात्र 10,128 मतों से जीत दर्ज की है। सबरीनाथन को 56,448 मत प्राप्त हुए।

चुनाव परिणाम पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री राजगोपाल ने कहा कि मैं उदास हूं कि हम दूसरे स्थान पर नहीं आ सके, लेकिन ओमन चांडी सरकार को स्पष्ट संकेत मिले हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि श्री राजगोपाल ने केरल में आधे दर्जन से अधिक चुनाव लड़े हैं और वह 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर से मात्र 15,000 मतों से हार गए थे। यही नहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री वी.मुरलीधरन ने कहा कि रूविक्कारा में हमारी एकमात्र पार्टी है, जिसके मतदाता आधार में इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि केरल में भाजपा के मतों की यह भारी वृद्धि तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब यहां पर लगभग दस महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।

त्रिपुरा में हुए दो सीटों के उपचुनाव में भाजपा कोई सीट जीत न सकी, लेकिन इस चुनाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह देखने को मिला कि दोनों सीटों पर भाजपा दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुचिंद्र दासगुप्ता ने दोनों सीटों पर भाजपा को हासिल मतों की संख्या में वृद्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि भाजपा त्रिपुरा में अब मुख्य विपक्षी पार्टी होगी और 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ माकपा ने प्रतापगढ़ (अनुसूचित जाति) और सुरमा (अनुसूचित जाति) विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रतापगढ़ सीट से रामू दास ने भाजपा की उम्मीदवार मौसमी दास को 17,326 वोटों से हराया। सीपीएम को 27,555 वोट, भाजपा को 10,229 जबकि कांग्रेस के रणजीत कुमार दास को 5,187 वोट मिले। सुरमा में सीपीएम के अंजन दास ने भाजपा के आशीष दास को 15,309 वोटों से हराया। सीपीएम को 23,275, भाजपा को 7,966 और कांग्रेस के नागेंद्र चंद्र विश्वास को 2,528 वोट मिले।

तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक प्रमुख और प्रदेश की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने 1.5 लाख मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। जयललिता ने चेन्नई के आर के नगर सीट पर 1 लाख 50 हजार 722 मतों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाकपा के सी महेंद्र को पराजित किया। महेंद्रन की अन्य उम्मीदवारों की तरह ही जमानत जब्त हो गई। मेघालय में चोकपोट विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की प्रत्याशी ब्लूबेल आर संगमा ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के फिलीपोल मराक को हराया। ■

भाजपा अध्यक्ष ने किया पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गठन

संगठन विस्तार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गठन करके संगठन विस्तार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल की है। यही नहीं, इस पहल से श्री शाह ने भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक समरसता की विचारधारा को भी मूर्त रूप देने का सराहनीय प्रयास किया है। ज्ञात हो कि पूर्व में संगठनात्मक दृष्टि से युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा- यह छह मोर्चे गठित करने का प्रावधान था। किंतु पहली बार पिछड़े वर्ग की भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 4 जुलाई को यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वर्तमान में, भारतीय समाज में पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी भागीदारी है। यही नहीं, यह वर्ग देश की सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका रखता है।

ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरे देश में भाजपा का व्यापक सदस्यता अभियान चलाया गया जो कि कई दृष्टियों से सफल अभियान था। इस अभियान के तहत लगभग 11 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और भारतीय जनता पार्टी विश्व पटल पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। इस सदस्यता अभियान में देश के सभी वर्ग और समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण की जो कि इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य था। ज्ञात हो कि पिछड़ा वर्ग पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है और देश के विभिन्न राज्यों में यह वर्ग प्रभावी रहा है किंतु उत्तर भारत में इस समुदाय की बहुत बड़ी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर भारत में चलाए गए सदस्यता अभियान में इस समुदाय के लोगों ने भी काफी बढ़-चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।

- **भाजपा अध्यक्ष द्वारा सामाजिक समरसता की विचारधारा को मूर्त रूप देने का सराहनीय प्रयास**
- **पाल-बघेल समाज के संघर्षशील नेता प्रोफेसर एस. पी. बघेल बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष**
- **भाजपा अध्यक्ष के इस नए कदम का देश भर के पिछड़ा वर्ग समाज ने किया स्वागत**

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह ने भाजपा के संगठन में सभी वर्गों के लोगों को नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के प्रभावी नेता एवं पूर्व सांसद, प्रो. एस. पी. बघेल को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है वहीं पूर्व सांसद डॉ. श्रीमती सुधा यादव को इस मोर्चे का प्रभारी नियुक्त किया है। प्रो. बघेल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। वे तीन बार लोकसभा के सांसद और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे। प्रो. बघेल ने एमएससी, एलएलबी तथा पीएचडी की उच्च शिक्षा ग्रहण की है। वे पाल बघेल समाज के संघर्षशील और व्यापक जनाधार वाले नेता हैं। वहीं, डॉ. श्रीमती सुधा यादव हरियाणा, गुड़गांव लोकसभा सीट से भाजपा की सांसद रही हैं एवं वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश के अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग सहित सभी समुदायों के सर्वांगिण विकास के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह का इसी दिशा में यह अभिनव प्रयास है। इससे जहां इस वर्ग का जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा वहीं निश्चित तौर से देश भर के पिछड़ा वर्ग समुदाय में भाजपा का जनाधार भी बढ़ेगा।

भाजपा अध्यक्ष के इस प्रयास का देशभर के पिछड़े वर्ग समुदाय में एक अच्छा संदेश गया है तथा पिछड़ा वर्ग समाज ने भाजपा अध्यक्ष के इस नए कदम का स्वागत किया है। ■

भाजपा संगठन में नई नियुक्तियों की घोषणा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रदेश प्रभारियों, सह प्रभारियों, मोर्चा प्रभारियों, विभिन्न विभागों सहित अनेक संगठनात्मक दायित्वों के लिए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की, जो निम्नलिखित हैः

क्र.	प्रदेश	प्रभारी	सह प्रभारी
1	आंध्र प्रदेश	श्री सिद्धार्थनाथ सिंह	
2	अंडमान निकोबार	श्री तरुण चुघ	
3	अरुणाचल प्रदेश	श्री रोमन डेका, सांसद	
4	असम	श्री महेन्द्र सिंह	
5	बिहार	श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद	श्री सी.आर. पाटिल, सांसद श्री पवन शर्मा
6	चण्डीगढ़	श्री प्रभात झा, सांसद	
7	छत्तीसगढ़	डॉ. अनिल जैन	
8	दादरा नगर हवेली	श्रीमती पूनम महाजन, सांसद	
9	दमन और दीव	श्री रघुनाथ कुलकर्णी	
10	दिल्ली	श्री श्याम जाजू	श्री तरुण चुघ
11	गोवा	श्री पुरुषोत्तम रूपाला	
12	गुजरात	श्री दिनेश शर्मा	
13	हरियाणा	डा. अनिल जैन	
14	हिमाचल प्रदेश	श्री श्रीकांत शर्मा	
15	जम्मू और कश्मीर	श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद	
16	झारखण्ड	श्री त्रिवेन्द्र रावत	श्री राम विचार नेताम
17	कर्नाटक	श्री मुरलीधर राव	श्रीमती पुरन्देश्वरी
18	केरल	श्री एच. राजा	श्री नलिन कटील, सांसद
19	लक्षद्वीप	श्री महेश गिरी, सांसद	
20	मध्य प्रदेश	श्री विनय सहस्रबुद्धे	
21	महाराष्ट्र	सुश्री सरोज पाण्डे	श्री राकेश सिंह, सांसद
22	मणिपुर	श्री प्रह्लाद पटेल, सांसद	
23	मेघालय	श्री नलिन कोहली	
24	मिजोरम	श्री पवन शर्मा	
25	नगालैण्ड	श्री फारूक खान	
26	ओडिशा	श्री अरुण सिंह	
27	पुडुचेरी	श्री महेश गिरी, सांसद	
28	पंजाब	श्री प्रभात झा, सांसद	
29	राजस्थान	श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद	श्री गोपाल शेट्टी, सांसद
30	सिक्किम	श्री रजनीश कुमार	
31	तमिलनाडु	श्री मुरलीधर राव	श्री सी.टी. रवि
32	तेलंगाना	श्री कृष्ण दास	
33	त्रिपुरा	श्री सुनील देवधर	
34	उत्तर प्रदेश	श्री ओ.पी. माथुर	श्री वीरेन्द्र खटीक, सांसद श्री रामेश्वर चौरसिया श्री रमेश बिधूड़ी सांसद श्री सुनील ओझा
35	उत्तराखण्ड	श्री श्याम जाजू	
36	पश्चिम बंगाल	श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री सुरेश पुजारी

क्र.	मोर्चा	प्रभारी
1	युवा मोर्चा	श्री मुरलीधर राव
2	महिला मोर्चा	श्रीमती पुरंदेश्वरी देवी
3	एससी मोर्चा	श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
4	एसटी मोर्चा	श्री रामविचार नीताम
5	अल्पसंख्यक मोर्चा	श्री फारूक खान
6	किसान मोर्चा	श्री सत्यपाल मलिक, श्री नित्यानन्द राय, सांसद (सह प्रभारी)
7	ओबीसी मोर्चा	श्रीमती सुधा यादव
1	किसान मोर्चा (अध्यक्ष)	श्री विजयपाल सिंह तोमर
2	ओबीसी मोर्चा (अध्यक्ष)	श्री एस.पी. सिंह बघेल

क्र.	विभाग	नाम
1	सुशासन, केन्द्र एवं राज्य शासकीय कार्यक्रम समन्वय	डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री महेश गिरि, श्री राज शेखर
2	नीति विषयक शोध	डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, श्री अनिर्बान गांगुली, श्री विक्षुत (कर्नाटक)
3	मीडिया	श्री श्रीकांत शर्मा
4	मीडिया सम्पर्क	श्री एम.जे. अकबर, श्री श्रीकांत शर्मा, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री अनिल बलूनी, श्री स्वदेश वर्मा
5	प्रशिक्षण	श्री मुरलीधर राव (प्रभारी), डॉ. महेश शर्मा (संयोजक), श्री सुनील पाण्डे (सह-संयोजक)
6	राजनैतिक प्रतिपुष्टी एवं प्रतिक्रिया	श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री एम.जे. अकबर,
7	राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठकें	डॉ. अनिल जैन, सरदार आर.पी. सिंह, श्री आर. पी. सिंह
8	डॉक्यूमेंटेशन एवं ग्रंथालय	डॉ. अनिल जैन, श्री अनिर्बान गांगुली, श्री सुनील पाण्डे
9	सहयोग एवं आपदीय राहत सेवाएं	श्री विजय गोयल, श्री नवीन सिन्हा
10	अध्यक्षीय कार्यालय, प्रवास एवं कार्यक्रम	श्री अरुण सिंह
11	प्रचार-साहित्य निर्माण	श्री श्याम जाजू, श्री विकास प्रीतम
12	ट्रस्ट समन्वय	श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
13	चुनाव प्रबन्धन	श्री भूपेन्द्र यादव
14	चुनाव आयोग सम्पर्क	श्री भूपेन्द्र यादव, प्रभारी श्री राजेन्द्र अग्रवाल (सांसद), श्री ओम पाठक, श्री रामाकृष्णन, श्री नरेन्द्र सावईकर, श्री राजन खोसला
15	कानूनी एवं विधिक विषय	श्री जगदीप धनकड़, श्री विक्रम बनर्जी, सुश्री एश्वर्या भाटी, श्री सागर
16	पार्टी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन	डॉ. शिवशक्ति बक्सी, श्री प्रभात झा, डॉ. सुधा मलैया, श्री बालाशंकर, श्री मुकेश मिश्रा
17	आई टी, वेबसाईट एवं सोशल मीडिया प्रबन्धन	श्री अमित मालवीय, श्री अरविंद गुप्ता
18	विदेश सम्पर्क	श्री विजय चौथाइवाला

1	सांगठनिक चुनाव के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी	श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद
1	संसदीय बोर्ड सचिव	श्री जे.पी. नड्डा
2	केन्द्रीय कार्यालय प्रभारी	श्री अरुण सिंह
3	जम्मू-कश्मीर सरकार से समन्वय	श्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं श्री राम माधव
4	प्रभारी आगामी असम विधानसभा चुनाव	श्री राम माधव
1	प्रवक्ता (आर्थिक मामले)	श्री गोपाल अग्रवाल